SC/ST and BC. The Government of India has not increased the post-matric scholarship, not introduced fee reimbursement for Other Backward Classes. Even for Other Backward Classes, there was no separate ministry or department. Providing mere reservation to OBCs is not enough. At the same time, they should also provide financial assistance, scholarships and facilities like fee reimbursement, hostels, Gurukul pathshala for special education. Both the Telugu States, Andhra Pradesh and Telangana, have provided many facilities to the SC/ST and BC students. At school level in Andhra Pradesh, Shri Jaganmohan Reddy has provided Rs.15,000 for every first class and second class student every year...*(Time-Bell rings)*...and the college students are getting Rs.20,000.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now Dr. Ashok Kumar Mittal. You have five minutes.

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने मुझे the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024 पर बोलने का मौका दिया। ये दोनों विधेयक हमारे समाज के आदिवासी और अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। एक ओडिशा से है, जिसमें

चार विमुक्त जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है और कुछ scheduled caste में आने वाली जातियों को scheduled tribe का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरे कानून में आंध्र प्रदेश की कुछ जातियों को scheduled tribe का दर्जा देने का निर्णय लिया जा रहा है। मैं इन दोनों कानूनों का पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि इन दोनों जातियों को इस status से बेहतर सुविधाएं, जैसे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं इस बड़े साहसिक कदम के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा और साथ ही उनको और पूरे देश को बधाई देना चाहूंगा।

(2X/DN पर जारी)

DN-DPS/2X/2.45

डा. अशोक कुमार मित्तल (क्रमागत) : हम सभी गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हम आदिवासी समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक positive कदम उठाएं और अपने आदिवासी भाई-बहनों की संस्कृति का अटूट हिस्सा बनें। जब हम environment conservation और loving mother earth की बात करते हैं, तो इससे अच्छा उदाहरण हमारे आदिवासी भाई ही हैं, और कोई नहीं हो सकता है, जो हमारे जंगल और environment को protect करने में भी हमारी मदद करते हैं।

हमारे आदिवासी समाज का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वे बिरसा मुंडा जी हों, अल्लूरी सीताराम राजू या तिलका मांझी हों। मैं इस

बिल का समर्थन करते हुए आदिवासी समाज के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उससे पहले मैं फिर हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने इस वर्ष आदिवासी मंत्रालय का बजट 13 हजार करोड़ रुपये कर दिया है - मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, आज भी हमारे आदिवासी समाज का literacy rate 59 प्रतिशत है, जो national average यानी 73 परसेंट से कम है। आदिवासी समाज हमारी जनसंख्या का 8 से 10 प्रतिशत है, लेकिन उनमें educational development कम है, जिसको सुधारने की जरूरत है।

महोदय, दूसरा मुद्दा tribal health का है। आज आदिवासी समाज में 13 प्रतिशत लोगों को डायबिटीज है, 25 प्रतिशत लोगों को ब्लड प्रैशर है, क्योंकि वहां डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी सुविधा के बारे में भी ध्यान दिया जाए। एक अन्य मुद्दा fake certificate का आता है, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार छिन जाते हैं और गलत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। अंत में मैं ओडिशा और आंध्र के आदिवासी समाज के लोगों को बधाई देता हूं कि आज उन्हें एक नया दर्जा मिलने जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे जो नॉर्थ-ईस्ट के आदिवासी भाई हैं, उनके बारे में थोड़ा सरकार सोचे और उन्हें भी बेहतर दर्जा देने की कोशिश करे, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Binoy Viswam; you have two minutes to speak. But I will give you five minutes. These two minutes' time is really very